ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 298-300**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत में UPI क्रांति का आर्थिक प्रभाव

डॉ0 माधवी शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र, महादेव रामस्वरूप डिग्री कॉलिज, बकैनिया भाट, मिलक, रामपुर (उ0प्र0) भारत

Received-17.12.2024, Revised-23.12.2024, Accepted-29.12.2024 E-mail: smadhvi590@gmail.com

सरांश : *'डिजिटल अर्थव्यवस्था आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्वरूप बन चुकी है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। भारत में डिजिटल क्रांति ने आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की है। विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारतीय भुगतान प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है।*

UPI ने नकद लेन–देन की आवश्यकता को कम करते हुए त्वरित, सुरक्षित एवं सरल डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित की है। इसके माध्यम से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं, ग्रामीण क्षेत्रों तथा असंगठित क्षेत्र को डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार से वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता, कर संग्रह, ई–कॉमर्स तथा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिला है। कोविड–19 महामारी के बाद डिजिटल भुगतान के उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे भारत विश्व की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया।

हालाँकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साइबर अपराध, डिजिटल असमानता, तकनीकी सुरक्षा तथा डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। प्रस्तुत लेख में डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा, भारत में न्च् क्रांति, उसके आर्थिक प्रभाव, लाभ, चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक असमानता और ग्रामीण समाज की प्रकृति एराजनीतिक शक्ति।

प्रस्तावना– 21वीं शताब्दी को डिजिटल युग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आर्थिक गतिविधियाँ भी इससे अछूती नहीं रहीं। आज बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर भुगतान तथा सरकारी सेवाएँ डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही हैं।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास विशेष रूप से 2014 के बाद तीव्र हुआ। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए "डिजिटल इंडिया अभियान" ने डिजिटल तकनीकों को जनसामान्य तक पहुँचाने का कार्य किया। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत की गई।

UPI ने मोबाइल आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली प्रदान कर आर्थिक लेन–देन को सरल, सुरक्षित तथा तेज बना दिया। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति केवल मोबाइल नंबर या QR कोड की सहायता से तत्काल भुगतान कर सकता है।

नोटबंदी (2016) तथा कोविड–19 महामारी के दौरान UPI का उपयोग तेजी से बढ़ा। आज भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक, हर स्तर पर डिजिटल भुगतान सामान्य हो चुका है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और UPI क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा– डिजिटल अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:

- डिजिटल बैंकिंग
- ऑनलाइन भुगतान
- ई–कॉमर्स
- डिजिटल सेवाएँ
- ऑनलाइन शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा प्रबंधन

डिजिटल अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी तथा सुलभ बनाना है।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास– भारत में डिजिटल विकास की प्रक्रिया धीरे–धीरे विकसित हुई, किन्तु पिछले दशक में इसमें तीव्र गति आई।

प्रमुख पहलें–

- डिजिटल इंडिया अभियान
- जन धन योजना
- आधार कार्ड प्रणाली
- मोबाइल इंटरनेट का विस्तार
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
- यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली

इन योजनाओं ने डिजिटल वित्तीय संरचना को मजबूत किया।

UPI की अवधारणा एवं कार्यप्रणाली– UPI (Unified Payments Interface) एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे National Payments Corporation of India द्वारा विकसित किया गया। यह प्रणाली बैंक खातों को मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ती है और तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

UPI की प्रमुख विशेषताएँ–

- तत्काल भुगतान

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

- 24×7 सेवा
- सुरक्षित एवं सरल प्रणाली
- QR कोड आधारित भुगतान
- न्यूनतम शुल्क
- बैंक खाते से सीधे भुगतान
- भारत में प्रमुख UPI ऐपकृ
- PhonePe
- Google Pay
- Paytm
- BHIM

ने डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

UPI क्रांति का आर्थिक प्रभाव–

1. नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: UPI ने नकद लेन–देन की आवश्यकता को कम किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण लोग मोबाइल के माध्यम से तुरंत भुगतान करने लगे हैं। इससे नकदी प्रबंधन की लागत में कमी आई तथा आर्थिक लेन–देन अधिक पारदर्शी बने।

2. वित्तीय समावेशन में वृद्धि: UPI ने ग्रामीण एवं गरीब वर्ग को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जन धन खातों, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की उपलब्धता ने करोड़ों लोगों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान की।

3. छोटे व्यापारियों को लाभ: UPI भुगतान प्रणाली ने छोटे दुकानदारों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ दिया। QR कोड आधारित भुगतान ने लेन–देन को सरल बना दिया। इससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई।

4. कर संग्रह में वृद्धि: डिजिटल भुगतान के कारण आर्थिक लेन–देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहने लगा। इससे कर चोरी में कमी आई तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। GST प्रणाली एवं डिजिटल भुगतान ने आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।

5. ई–कॉमर्स का विकास: UPI ने ऑनलाइन खरीदारी को आसान बनाया। ई–कॉमर्स कंपनियों को डिजिटल भुगतान से बड़ा लाभ मिला। ऑनलाइन व्यापार, फूड डिलीवरी तथा डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ।

6. बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन: UPI ने पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल बैंकिंग में परिवर्तित कर दिया। अब लोग बैंक शाखाओं में जाने के बजाय मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं।

7. महिला सशक्तिकरण: डिजिटल भुगतान प्रणाली ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ स्वयं डिजिटल भुगतान का उपयोग करने लगी हैं, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी है।

कोविड–19 और डिजिटल भुगतान– कोविड–19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। संपर्क रहित भुगतान (Contactless Payment) की आवश्यकता के कारण UPI लेन–देन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। सरकारी सहायता राशि भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। इससे DBT प्रणाली को मजबूती मिली।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव–

1. GDP वृद्धि में योगदान: डिजिटल अर्थव्यवस्था ने व्यापारिक गतिविधियों को गति प्रदान की, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला।

2. स्टार्टअप संस्कृति का विकास: UPI आधारित फिनटेक कंपनियों के विकास से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिला। भारत विश्व का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनता जा रहा है।

3. रोजगार के अवसर: डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आईटी, फिनटेक, ई–कॉमर्स तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए।

4. पारदर्शिता एवं सुशासन: डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भ्रष्टाचार को कम करने तथा सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता की।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ–

1. साइबर अपराध: डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी तथा डेटा चोरी की घटनाएँ भी बढ़ी हैं।

2. डिजिटल असमानता: ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट एवं तकनीकी सुविधाओं की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है।

3. डेटा गोपनीयता: डिजिटल लेन–देन में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटा लीक एवं हैकिंग का खतरा बना रहता है।

4. तकनीकी निर्भरता: डिजिटल प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता के कारण तकनीकी खराबी होने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

सरकार की भूमिका– भारतीय सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाएँ लागू की हैं:

- डिजिटल इंडिया अभियान
- आधार आधारित भुगतान प्रणाली
- भारतनेट परियोजना
- साइबर सुरक्षा कार्यक्रम
- फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहन

इन योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना है।

भविष्य की संभावनाएँ– भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है।

संभावित विकास क्षेत्र–

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

- ब्लॉकचेन तकनीक
- डिजिटल बैंकिंग
- ग्रामीण डिजिटल सेवाएँ
- कैशलेस अर्थव्यवस्था

यदि डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा एवं इंटरनेट पहुँच को और मजबूत किया जाए, तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त बन सकती है।

निष्कर्ष– डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं UPI क्रांति ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। इसने भुगतान प्रणाली को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया है। UPI ने वित्तीय समावेशन, कर संग्रह, व्यापारिक गतिविधियों तथा डिजिटल बैंकिंग को नई दिशा प्रदान की है। भारत आज डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। हालाँकि साइबर अपराध, डिजिटल असमानता एवं डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, किन्तु उचित नीतियों एवं तकनीकी सुधारों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान संभव है। भविष्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्त एवं सुंदरम – भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. मिश्रा एवं पुरी – भारतीय अर्थव्यवस्था।
3. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट।
5. डिजिटल इंडिया रिपोर्ट।
6. National Payments Corporation of India (NPCI).
7. Reserve Bank of India.
8. Ministry of Electronics and Information Technology.
9. योजना पत्रिका, डिजिटल भारत विशेषांक।
10. कुरुक्षेत्र पत्रिका।
11. विश्व बैंक रिपोर्ट।
12. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) रिपोर्ट।

*****